

सम्पादकीय

नीट का विरोध, तमिलनाडु विधानसभा का प्रस्ताव

तमिलनाडु विधानसभा नीट परीक्षा के विरोध में प्रस्ताव पास हुआ है। राज्य में मेडिकल, डैंटल आदि के लिए होने वाली अखिल भारतीय प्रवेश परीक्षा नीट (नेशनल एंट्रेस-कम-एलिजिबिलिटी टेस्ट) से बाहर होने की मंशा जताई है। तमिलनाडु विधानसभा ने लगभग सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर मेडिकल, डैंटल आदि के लिए होने वाली अखिल भारतीय प्रवेश परीक्षा नीट (नेशनल एंट्रेस-कम-एलिजिबिलिटी टेस्ट) से बाहर होने की मंशा जताई है। राज्य सरकार चाहती है कि प्रदेश में 12वीं बोर्ड परीक्षा के अंकों को ही मेडिकल और डैंटल कॉलेजों में एडमिशन का आधार बनाया जाए। न केवल सत्तारूढ़ डीएमके और विपक्षी दल एआईएडीएमके बल्कि पीएमके और कांग्रेस समेत तमाम पार्टियों ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया। एकमात्र अपवाद बीजेपी रही, जो सदन से वॉकआउट कर गई। सदन में दिखी यह भावना अकारण नहीं है। तमिलनाडु में नीट का विरोध पहले से होता रहा है। डीएमके ने हालिया विधानसभा चुनावों के दौरान कहा था कि अगर उसकी सरकार बनी तो राज्य में नीट समाप्त कर दिया जाएगा। सरकार बनने के एक महीने के अंदर राज्य में नीट के प्रभावों का अध्ययन करने के लिए अवकाश प्राप्त न्यायाधीश एके राजन की अध्यक्षता में एक समिति गठित कर दी गई। समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि अगर कुछ साल और नीट की व्यवस्था लागू रही तो राज्य का स्वास्थ्य ढांचा चरमरा जाएगा और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और सरकारी अस्पतालों में तैनात करने के लिए डॉक्टर कम पड़ने लगेंगे।

राज्य की डीएमके सरकार ने विधानसभा में प्रस्ताव पेश करने के फैसले का आधार इसी रिपोर्ट को बनाया है। लेकिन ध्यान रहे, एआईडीएमके जब शासन में यी तो उसने भी विधानसभा में ऐसा ही प्रस्ताव पारित करवाया था। राष्ट्रपति की मंजूरी न मिलने की वजह से उस प्रस्ताव पर अमल नहीं हो पाया। इस बार भी प्रस्ताव के अमल में आने के लिए राष्ट्रपति की मंजूरी की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि अखिर तर्मिलनाडु में नीट की काइतना विरोध क्यों है। राज्य सरकार का कहना है कि नीट की पद्धति में अलग-अलग पृष्ठभूमि के छात्रों के साथ न्याय नहीं हो पाता है। 12वीं में मिले अंकों के आधार पर एडमिशन देने के पक्ष में उसकी दलील है कि मेडिकल एडकेशन का स्तर ऊंचा बनेगा रहना एडमिशन प्रक्रिया पर निर्भर नहीं करता। बहरहाल, नीट को लेकर शिकायतें तमिलनाडु तक सीमित नहीं हैं। अन्य राज्यों से भी शिकायतें आती रही हैं। यह कहा जाता रहा है कि नीट लागू होने के बाद से देश भर में कौचिंग कलासेज की जकड़न मजबूत हुई है। बगैर कौचिंग के मेडिकल एंट्रेस क्लीयर करना मुश्किल हो गया है। इससे आर्थिक रूप से कमज़ोर तबकों और ग्रामीण पृष्ठभूमि के युवाओं विचित महसूस कर रहे हैं। यही हाल गैर-हिंदू भाषी युवाओं का है। ये शिकायतें वाजिब हो सकती हैं। लेकिन इसका हल यह नहीं हो सकता कि राज्य सरकारें इससे निकलने का फैसला करने लगाएं। ज़रूरत इस बात की है कि सब मिलकर इस व्यवस्था की गड़बड़ियों को चिह्नित करें और उन्हें दूर करने की कोशिश करें ताकि देश भर के प्रतिभाशाली युवा खुद को साबित करने का मौका पाएं और उसका बेहतरीन इस्तेमाल कर सकें।

असुरक्षा भाव से घिर चुकी हैं भाजपा

राकेश अचल

भाजपा का भयभीत होना विषयक और देश की आर्तनाद कर रही जनता के लिए शुभ हो सकता है किन्तु गैरकांग्रेसवाद के लिए नहीं। भाजपा का भय देश की सियासी तस्वीर के रंग भी बदल सकता है और विषयक की किस्मत भी। भारत की राजनीति में रुचि रखने वाले दुनिया के तमाम देश भाजपा के चेहरे से ज्ञाकर्ते भय पर अपनी निगाहें लगाए हुए हैं। हम और आप तो इसके चश्मदीद गवाह तो हैं ही। गुजरात के बाद कहाँ के नेता बदले जायेंगे, यह अभी से कहना उचित नहीं है। ब्रे 132 करोड़ की आबादी वाले महादेश का भविष्य बीते सात साल से जिसका भारतीय जनता पार्टी के हाथों में है, वह स्वयं अब बुरी तरह से असुरक्षा भाव से घिर चुकी है। अपने चेहरे की भी परचाई मिटाने के लिए भाजपा का शीर्ष नेतृत्व अब शीर्षासन करता नजर आ रहा है। विषयक के लिए यह सुखद हो सकता है लेकिन समूचे परिदृश्य के लिए यह शुभ घटना नहीं है। पिछले कछ वर्षों में एक के बाद एक हार से आतंकित भाजपा जहां देश और दुनिया के सामने गुजरात मॉडल का ढोल पीटना भूल गयी है, वहीं उसे अब गुजरात की चिंता भी सताने लगी है। हाल ही में गुजरात में हुए नेतृत्व परिवर्तन ने भाजपा को भी भयग्रस्त प्रमाणित कर दिया है। भाजपा हाल ही में कर्नाटक और उत्तराखण्ड में भी नेतृत्व परिवर्तन के लिए विवश हो चुकी है। जिस गुजरात में आज के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने एक मुख्यमंत्री के रूप में पूरे पंद्रह साल एकछत राज किया था, उसी गुजरात में बीते सात साल में दो मुख्यमंत्री बदले जा चुके हैं। जाहिर है कि अब गुजरात देश के लिए मॉडल नहीं रहा।

राजनीति परिस्थितियों का आकलन करें तो आप पाएंगे कि भाजपा का शीर्ष नेतृत्व हाल ही में बंगाल विधानसभा चुनाव में मिली पराजय के बाद से एकदम विचलित हो गया है। भाजपा को अब उत्तर प्रदेश के साथ-उन तमाम राज्यों के विधानसभा चुनावों की विंता भी सताने लगी है जहां

अगले साल जनादेश के लिए मैदान में उत्तरना है। गुजरात में भाजपा व पतली हालत के बाद भाजपा ने गुजरात के बजाय उत्तर प्रदेश को अपन मॉडल राज्य बताना शुरू कर दिया है। प्रधानमंत्री से लेकर भाजपा टे राष्ट्रीय अध्यक्ष तक उपर के मुख्यमंत्री का सुतिगण करते दिखाई दे रहे हैं। यह अब साफ़ दिखाई दे रहा है कि राजनीति को करवट बदलते दे नहीं लगती। पिछले दो साल में तमाम आंतरिक गड़बड़ियों के बावजूद जहां कांग्रेस ने राजस्थान, पंजाब और छत्तीसगढ़ में नेतृत्व परिवर्तन नहीं किया, वहां भाजपा को एक के बाद एक तीन राज्यों में अपने मुख्यमंत्र बदलने पड़े। जाहिर है कि कमजोर विपक्ष का दाग लिए धूम रहीं कांग्रेस आंतरिक असंतोष झेलने के मामले में भाजपा से कहीं ज्यादा बेहत साबित हुई है। भाजपा के लिए अब उत्तर प्रदेश एक विवशता बन चुका है। उपर को जीते बिना भाजपा केंद्र की सत्ता को बचाकर नहीं रख सकती।

अजीबोगरीब लग सकता है किन्तु अब यह एक हकीकत है कि गुजरात के शेर अब उत्तर प्रदेश में विहार करने के लिए विवश हैं। काशी छोड़कर साबरमती की ओर रुख नहीं कर सकते क्योंकि काशी की गंगा साबरमती के मुकाबले अब ज्यादा महत्वपूर्ण हो चुकी है। भाजपा का शीर्ष नेतृत्व यह मान चुका है कि यदि उत्तर प्रदेश में भी बंगाल टेन नीजे आये तो भाजपा को दिल्ली छोड़ना पड़ेगी। इसलिए किसी भी भाजपा शासित राज्य से कमजोरी की खबर नहीं आनी चाहिए। गुजरात में भाजपा का शासन बदनामी का कारण बन रहा था इसलिए विजय रूपाणी को बदलने में एक पल की भी देर नहीं की गयी। उत्तराखण्ड रभी सियासी भूस्खलन की खबरें आनी शुरू हो गयी थीं, सो वहां भी नेतृ बदलकर मरम्मत कर दी गयी। मुख्यमंत्रियों को बदलना किसी भी पार्टी का अंदरूनी मामला है। इसका जनादेश से अब कोई संबंध नहीं रह गया है। लोकतंत्र से तो बिलकुल नहीं। जनता ने किस नेता का मुंह देखकर जनादेश दिया था, यह पूछने वाला कोई नहीं है। पूछिए भी तो कोई जवाब देने वाला नहीं है। कांग्रेस ने यह परम्परा बनाई थी और भाजपा ने इ

जस का तस स्वीकार कर लिया है। अर्थात् राज्यों पर मुख्यमंत्री थोपना ही आज का लोकतंत्र है। कांग्रेस की इस परम्परा से आज भाजपा सुविधा अवश्य अनुभव कर रही होगी किन्तु इससे भाजपा की चाल, चरित्र और चेहरे की वास्तविकता बैनकाब जरूर हो गयी है।

भाजपा बंगाल को सोनार बांगला नहीं बना पाई लेकिन उसे अब उत्तरप्रदेश में रामराज्य स्थापित करके दिखाना ही होगा। भाजपा येन केन प्रकारेण उत्तर प्रदेश में रामराज के लिए राम मंदिर निर्माण की आधारशिला पहले ही रख चुकी है किन्तु किसान आंदोलन की वजह से इस कसरत का फल फीका होता नजर आ रहा है। देश के किसान जगह-जगह पिट-पिटाकर अब उत्तर प्रदेश में जमावड़ा तैयार कर रहे हैं। एक साल से सड़कों पर सघर्ष कर रहे किसानों की समझ में आ गया है कि भाजपा सरकार की जिद को बेअसर करने के लिए उसे उत्तर प्रदेश से उखाइना ही होगा। आने वाले दिनों में यदि आंदोलनरत किसान खुदा न खस्ता खुद ही चुनाव मैदान में कूद गए तो भाजपा का 2024 का पूरा गणित खराब हो सकता है। भाजपा के लिए बंगाल से बड़ी चुनौती उत्तर प्रदेश में पेश आने वाली है। विपक्ष के लिए भी उत्तर प्रदेश का मार्चा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। हाशिये पर खड़ी कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी या बहुजन समाज पार्टी- सभी को उत्तर प्रदेश का आशीर्वाद चाहिए। यही दबाव है कि बसपा को अपने बाहुबली नेताओं से हाथ जोड़ने पड़ रहे हैं। ऐसे अत्यसंख्यक नेताओं के लिए हैंदराबादी बिरयानी मंच सजाकर खिलाने की तैयारी ओरैसी ने कर रखी है। कुल जमा बात भाजपा की भी है। भाजपा का भयभीत होना विपक्ष और देश की आर्तनाद कर रही जनता के लिए शुभ हो सकता है किन्तु गैरकांग्रेसवाद के लिए नहीं। भाजपा का भय देश की सियासी तस्वीर के रंग भी बदल सकता है और विपक्ष की किस्मत भी। भारत की राजनीति में रुचि रखने वाले दुनिया के तमाम देश भाजपा के घेरे से ज़ाकते भय पर अपनी निगाहें लगाए हुए हैं। हम और आप तो इसके चश्मदीद गवाह तो हैं ही। गुजरात के बाद कहाँ के नेता बदले जायेंगे, यह अभी से कहना उचित नहीं है।

ओबीसी सियासत बदल रही समीकरण

नरेंद्र नाथ

पिछले कुछ दिनों से ओबीसी और इससे जुड़े मुद्दों पर सियासत केंद्र में आ गई है। इसका असर राजनीतिक दलों के अंदर संगठन और नेतृत्व पर भी पड़ने लगा है। सभी दलों के अंदर ओबीसी नेताओं की पूछ बढ़ने लगी है। संगठन में ओबीसी की हिस्सेदारी बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। साथ ही, ओबीसी वोट को प्रभावित करने वाले छोटे-छोटे दलों को भी अपने पक्ष में करने के लिए तमाम बड़े राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दल अचानक सक्रिय हो गए हैं। सभी दलों का आकलन है कि 2024 में जिस सियासी ठीम में जितने मजबूत ओबीसी खिलाड़ी होंगे, उसे उतना ही लाभ मिलेगा और वह चुनावी पिच पर बेहतर स्कोर कर पाएगी। ओबीसी नेतृत्व को अपने पाले मैं करने की कोशिश का असर चुनावी राज्यों में भी दिखने लगा है। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव को भी अपनी पुरानी सियासी गलती का अहसास हो रहा है। मुलायम सिंह यादव के समय ओबीसी का बड़ा तबका समाजवादी पार्टी के साथ था, लेकिन बाद में इसमें यादव और गैर-यादव ओबीसी के बीच दूरी बढ़ती गई और एसपी का यह वोट छिटक कर बीजेपी के पास चला गया। बीजेपी ने मौका देखकर 2017 में गैर-यादव ओबीसी का तकरीबन सारा वोट अपने पक्ष में कर लिया और बड़ी जीत हासिल की। इस बार अखिलेश यादव ओबीसी की इन छोटी-छोटी जातियों के बीच खोया जनाधार पाने के लिए इनके नेताओं तक पहुंच बना रहे हैं। उधर, बीजेपी अपनी पकड़

किसी भी सूरत में कम करने को तैयार नहीं है। राज्य में चुनाव से पहले ओम प्रकाश राजभर, संजय निषाद, अनुप्रिया पटेल, संजय चौहान जैसे नेताओं की बढ़ती पूछ भी इसी ट्रैड का परिणाम है। बीजेपी कल्याण सिंह के निधन के बाद उनके सम्मान के बहाने अपनी ओबीसी नेताओं को एक मंच पर करने की कोशिश कर रही है। वही मायावती ने अपनी पार्टी के अंदर ब्राह्मण और ओबीसी नेताओं का अधिक तरजीह देने की रणनीति बनाई है। माना जा रहा है कि इस बाचुनाव में टिकट बंटवारे में ओबीसी नेताओं को सबसे अधिक लाभ मिल सकता है। उसी तरह अभी छतीसगढ़ में जब भूपेश बघेल बनाम टीएस सिंह देव के बीच सीएम पद को लेकर गुटबाजी हुई तो बघेल का मजबूत ओबीसी नेता होना ही उनके पक्ष में गया। पार्टी के अंदर आप राय बनाने कि मौजूदा माहौल में बघेल जैसे ओबीसी नेता को अस्थिर करने का जोखिम नहीं लिया जा सकता। उधर, बीजेपी नेतृत्व छतीसगढ़ में संदेश दे रहा है कि अगर बीजेपी चुनाव जीती तो कोई ओबीसी ही सीएम बनेगा। बगल के राज्य मध्य प्रदेश में भी ओबीसी केंद्रित राजनीति अभी केंद्र में है। जहां कांग्रेस जीतूँ पटवारी जैसे युवा नेताओं को प्रमोट कर रही है, वहीं शिवराज सिंह चौहान खुद को ओबीसी नेता बताते हुए सियासी संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। बिहार में आरजेडी ने ओबीसी को अपने पक्ष में करने के लिए विशेष अभियान तक छेड़ दिया है। पार्टी ने कहा कि ओबीसी चेहरों को मीडिया से लेकर मंच तक अधिक से अधिक मौका देगी। तेजस्वी यादव के सामने भी अखिलेश यादव की तरह गैर-यादव ओबीसी को जोड़ने की चुनौती है। बिहार में

तेजस्वी यादव ने भी मस्लिम-यादव के अपने पारंपरिक समीकरण से निकलकर पार्टी में ओबीसी नेताओं को अधिक तरजीह देने की रणनीति बनाई है। उधर, नीतीश कुमार एक बार फिर से खुद को ओबीसी नेता के रूप में स्थापित करने के लिए एक को बाद एक कई राजनीतिक दाव खेलने की कोशिश कर रहे हैं। महाराष्ट्र हो या मध्य प्रदेश इन राज्यों में भी अभी ओबीसी चेहरों को कांग्रेस और बीजेपी तरजीह देने की रणनीति बना रही है। दरअसल, विपक्ष 2024 आम चुनाव से पहले ओबीसी वोटरों के बीच अपनी पहुंच बना लेना चाहता है। उसका मानना है कि अगर वह ओबीसी वोटरों में अपनी स्थिति नहीं सुधार सका तो उसके लिए आने वाले दिनों में दिक्कत और बढ़ेगी। ओबीसी वोटरों तक पहुंच बनाने के लिए इन दलों के अंदर मजबूत ओबीसी नेतृत्व की भी जरूरत होगी। संख्या के लिहाज से भी यह सबसे बड़ा समूह है। हाल के दिनों में बीजेपी ने इस वोटर समूह को अपने पक्ष में करने के लिए एक के बाद एक कई कदम उठाए हैं। नेतृत्व में जगह भी दी है। पिछले दिनों जब मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में मंत्रिमंडल विस्तार हुआ तो सबसे अधिक ओबीसी नेताओं को ही जगह दी गई और इसे बहुत प्रचारित भी किया गया। दरअसल, पिछले कुछ दिनों से देश की सियासत में एक के बाद एक ऐसी घटनाएं हुईं, जिनसे ओबीसी राजनीति केंद्र में आ गई। पहले जातीय जनगणना की मांग को मुदा बनाया गया। तमाम क्षेत्रीय दल इस मांग को लेकर बीजेपी पर दबाव बढ़ाने लगे तो इसका असर सरकार पर भी दिखा। समांतर रूप से रोहिणी कमिशन की रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग की जा रही है।

अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी के बाद भारत में आतंकी घटनाएं बढ़ने की आशंका है, क्या वाकई ऐसा होगा

अजय साहनी

आतंकवाद के उभार के रूप में। थोड़े वर्त के लिए इस्लामिक स्टेट या दाएश उभरकर आ गया, जिसने बड़े इलाके पर कब्जा कर लिया और दुनिया भर में आतंकवाद को बढ़ाया। 2014 में वैश्विक आतंकवाद चरम पर था। इसमें सबसे ज्यादा सक्रिय था दाएश, लेकिन उसके बाद से इस संगठन का असर कम होता गया है। अदेशा जताया गया था कि 2017 में दाएश के पतन के बाद घर लौटने वाले हजारों लड़ाके पश्चिम में हिंसा का दौर ला देंगे। हालांकि ऐसा कुछ नहीं हुआ। इन अनुमानों के बावजूद अमेरिका या यूरोप में कोई संगठित आतंकवादी हमला नहीं हुआ है। अब पश्चिम में प्रमुख खतरा है घरेलू दक्षिणपंथी आतंकवाद। दुनिया में चल रही इन घटनाओं से भारत भी प्रभावित हुआ। 2001 में जब अमेरिका पर हमला हुआ था, वह साल आतंकवाद के लिहाज से भारत के लिए भी सबसे बुरा साबित हुआ। उस बरस 5504 लोगों की आतंकवादी घटनाओं में मौत हुई। केवल जम्मू-कश्मीर में ही 4011 जाने गई। 2011 के बाद देशभर में होने वाली मौतों में कमी आई है। 2020 में यह संख्या घटकर 591 रह गई थी और इस साल पांच सितंबर तक आंकड़ा 366 है। जम्मू-कश्मीर में 2012 में सबसे कम जाने गई, केवल 121। हालांकि बाद में इनकी संख्या बढ़ी। इस साल 5 सितंबर तक 162 लोग आतंकवाद से जुड़ी घटनाओं में जान गंवा चुके हैं। इन मामलों के बढ़ने की वजह है धृवीकरण की राजनीति और सदिगद्य घरेलू नीतियां।

ओसामा बिन लादेन ने 1996 में अल कायदा की ओर से भारत में जिहाद का आह्वान किया था। इसके बाद कई बार इसी तरह की अपील की गई। साल 2014 में इस क्षेत्र के लिए अल कायदा ने एक संगठन खड़ा किया। जम्मू-कश्मीर में कुछ सफलता के बावजूद अंसार गजवत-उल-दिन्द कोई प्रभारी जेटर्क बनाने में तिफ़िल रहा। यह भारतीय जमीन पर

कोई बड़ी वारदात नहीं कर सका है। दाएश ने जून 2014 में अपना नक्शा जारी किया था। यह नक्शा दिखाता था कि इस आतंकी संगठन के दुनिया में प्रभुत्व कहां है। इसमें भारत को 'विलायत खुरासान' के हिस्से के रूप में शामिल किया गया था। इससे इस आशंका को बल मिला तिबड़े पैमाने पर आतंकवादी हमले हो सकते हैं। तब से सात बरस बीत चुके हैं। दाएश या उसके सहयोगी संगठनों ने कोई बड़ी वारदात नहीं की। दाएश से प्रभावित एक युवा ने एक घटना को जरूर अंजाम दिया था। सात मार्च 2017 को भोपाल-उज्जैन पैसेंजर ट्रेन में एक धमाका किया गया। इसमें 12 यात्री घायल हुए। दाएश के घटते असर का एक सबूत यह भी है कि केवल 169 भारतीय नागरिक इसमें शामिल होने के लिए इराक, सीरिया या अफगानिस्तान गए थे। इनमें से 56 के मारे जाने के पुष्टि हो गई है। हकीकत यह है कि पाकिस्तान की जमीन से संचालित हो गाले और वहां से समर्थन प्राप्त इस्लामिक आतंकवादी संगठन ही भारत देश लिए प्रमुख खतरा हैं। पिछले दो दशकों में वे भी अपना असर खो चुके हैं। इसके पौछे इस्लामाबाद पर अंतरराष्ट्रीय दबाव बढ़ने समेत कई दूसरे कारण हैं। एक उड़ात हुआ अनुमान लगाया जा रहा है कि अफगानिस्तान में जेहादी की लड़ाई लड़ रहे आतंकी अब खाली हो चुके हैं। अफगान जीत के बाद इनका रुख जम्मू-कश्मीर की ओर हो सकता है। जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद इस वजह से कम नहीं हुआ, क्योंकि पाकिस्तान में लोग नहीं थे या उसके पास संसाधनों की कमी हो गई थी। आतंकी घटनाओं में गिरावट की वजह से रही भारतीय सेना और स्थानीय स्तर पर उसे मिला समर्थन। अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी के बाद इस आशंका को सिरे से खारिज कर देना नासमझी होगी कि आतंकी घटनाएं बढ़ सकती हैं। इसी तरह घबराक किसी जिज्ञासु पर पहुंचना भी नासमझी देगी।

बादशाह और वजौर को वह अजब-गजब जोड़ी

ਕ੃਷ਣ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿਹ

में नवाबों के राज में गाजीउद्दीन हैदर

ज्ञा जायज है लेकिन अमरिंदर हरियाणा
नुकसान क्यों पहुँचवाना चाहते हैं?

अमरिंदर हरियाणा वाना चाहते हैं?

राकेश सैन

साफ हो गया है कि यह पूरा आन्दोलन कांग्रेस और पंजाब प्रायोजित है। कैप्टन को पंजाब के साथ हरियाणा और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की भी चिन्ता करनी चाहिए। उनको किसान संगठनों को समझाना चाहिए। पूर्व केन्द्रीय मन्त्री व अकाली दल की नेता हरसिमरत कौर बादल ने इस बयान पर कहा कि कैप्टन अपने आलीशान महल में आराम करते हैं, जबकि हमारे किसान पिछले 10 महीने से खराब मौसम में दिल्ली की सड़कों पर मर रहे हैं। यही कैप्टन की योजना थी। होशियारपुर में एक सरकारी कार्यक्रम में बोलते हुए कैप्टन अमरिन्दर ने किसानों को अपील की कि वह पंजाब में 113 जगह दिए जा रहे धरने उठा लें, ताकि आम लोगों को राहत मिल सके और पंजाब की आर्थिकता प्रभावित न हो। कहीं न कहीं यह धरने पंजाब के लिए गम्भीर साबित हो रहे हैं। राज्य की आर्थिक हालात पहले ही ठीक नहीं हैं और अगर किसान अपने ही राज्य में धरने लगाएंगे तो इससे हालत और खराब हो सकती है। उन्होंने

जिन्हें बावजूद उन्होंने 'उफ' तक नहीं की, न ही वजारत छाड़ी। गाजीउद्दीन भी 'सत्तनत की लूट' के बावजूद उन्हें लंबे वक्त तक सहते रहे। दरअसल, आगामीर गाजीउद्दीन के बचपन के दोस्त थे, दोस्ती को ऐसी वैसी नहीं हम-निवाला-हम-प्याला थी। इसलिए उन्होंने गदी पर बैठते ही उनको उजीर बना दिया था। गोकिं वह उनकी रण-रण वाकिफ थे। बाद में अंग्रेज गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्ज के बहकाम में आकर उन्होंने खुद को 'दिल्ली के दबदबे से आजाद अवध क्षत्रिय बादशाह' घोषित कर दिया तो कहते हैं कि आगामीर ही सबसे ज्यादा खुश हुए थे। यह सोचकर कि बेलागाम बादशाह की लगातार अब एकमात्र उन्हीं के हाथ रहेगी।

प्रसंगवश, मीर तकी तुकमानी के बेटे आगामीर का माता-पिता का दिया नाम सैयद मुहम्मद खां था। वजीर बने तो उन्हें मोतमउद्दैल मुख्जार-उल-मुल्क सैयद मुहम्मद खां बहादुर उर्फ आगामीर का खिताब मिला, जो बाद में आगामीर भर रह गया। इतिहासकार बताते हैं तिंह उन्होंने ऐसी विलक्षण बुद्धि पाई थी, जो सूबे का खजाना भरने के करामात में तो उनकी मदद करती ही थी, अपना घर भरने से भी मन नहीं करती थी। अपनी वजारत के दौरान उन्होंने सूबे का खजाना इतना भर दिया था कि वह उन दिनों खस्ताहाल ईस्ट इंडिया कंपनी को बड़े-बड़े कर्ज दिया करते। इतना ही नहीं, उन्होंने लखनऊ में अपने नाम की एक ड्यूढ़ी भी बनवाई थी, जो आज उसके एक मुहल्ले का नाम है। यह ड्यूढ़ी बन रही थी तो उन्होंने एक इत्रफरोश से उसका सारा इतना खरीदकर उसे गारे में मिलवाया और उसी से दीवारों का पलस्तर करवाया ताकि दीवारें दूर-दूर तक खुशबू बिखेरती रहें। उन्होंने अपने नाम से एक सराय भी बनवाई थी। नवाबी के जलवे' नाम की किताब में लिखा है कि एक समय सूबे में आगामीर की मर्जी के बांग पता तक नहीं हिलता था और उनकी करामात की चुंड़ओर चर्चा होती थी। लेकिन एक बार बादशाह ने एक आदमी से खुश होकर उसे दरबार में नौकरी देनी चाही तो वह परेशान हो उठे। दरअसल, वह आदमी उनके कई भेद जानत था और बादशाह पर खोल सकता था। इसलिए उन्होंने पहले तमामले को भरपूर टाला फिर कह दिया कि वह आदमी तो खुदा का प्यारा हो गया। लेकिन एक दिन बादशाह सुबह की सैर पर गए तब वह आदमी उन्हें दिख गया। उन्होंने आगामीर से उसे बुलाने को कहा तो उन्होंने उनसे पूछा, 'कैसे बुलाऊं हुजर? उसे तो आप अपने चश्मा दैन (चाई-कैप) से दैन नहीं।'

